बीफ-बीफ मत चिल्लाओ, हिम्मत है तो हिंदू कंपनियों का मांस निर्यात बंद कराओ

-वाई.के. रज्जन

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बेचारे इन दिनों बहुत बड़े धर्म संकट में हैं। हरियाणा में औद्योगिक निवेश के लिए वो मार्च में गुड़गांव में विदेशी कंपनियों को बुला रहे हैं। विदेशी कंपनियों के सीईओ ने खट्टर से कहा कि आपके राज्य में तो सरकार तय कर रही है कि लोग क्या खायें और क्या न खायें तो निवेश करने के लिए क्यों आयें...परेशान मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों बयान दे डाला कि अगर कोई विदेशी बीफ खाना चाहे तो उन्हें स्पेशल लाइसेंस देकर यह छूट दी जा सकती है। अचानक उदार बन गए खट्टर साहब ने यह भी कह डाला कि खानपान तो निजी चीज है, उसमें सरकार क्यों दखल दे।...जिसने भी सीएम का बयान देखा, वह हैरान। क्योंकि दो महीने पहले इस शख्स की सरकार ने बहुत कठिन गोरक्षा कानून लागू किया है। जिसमें कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। ...यह वही शख्स है जिसने 6 महीने पहले कहा था कि जिन्हें बीफ खाना है, उन्हें पाकिस्तान जाना होगा।...खट्टर ने किन हालात में अपना नया उदार बयान दिया, इसकी सच्चाई तो हरियाणा में निवेश करने के लिए आने वाली कंपनियों के आने के बाद ही पता चलेगी लेकिन आरएसएस को यह बात पसंद नहीं आई। संघ ने अपने चंपुओं को फौरन आदेश दिया कि खट्टर के बयान का जवाब दिया जाये। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज समेत तमाम के बयान आ गए कि किसी भी कीमत पर बीफ खाने की अनुमति नहीं मिलेगी, चाहे वो स्पेशल हो या आम हो। ...खट्टर को संदेश चला गया। खट्टर ने भी पलटी मारी और कहा कि सरकार ने बीफ पर अपना नजरिया नहीं बदला है। कानून का सख्ती से पालन होगा। यानी खट्टर ने एक तरह से अपना उदार बयान वापस ले लिया।

हरियाणा के मुख्यमंत्री पिछले दिनों चीन, जापान और अमेरिका में जिन जगहों पर विदेशी कंपनियों को राज्य में उद्योग लगाने का न्यौता देने गए थे, उन सभी जगहों पर सांप, नेवला, केकड़ा से लेकर, कुत्ता और न जाने किन-किन जानवरों का मांस खाया जाता है। विदेशी कंपनियों जब कहीं निवेश करती हैं तो वो उस राज्य के इन्फ्रास्ट्रक्चर (सड़क, बिजली, पानी और इनसे जुड़ी अन्य चीजें) के अलावा धार्मिक आजादी और माहौल को भी देखती हैं। माहौल का हाल यह है कि आईबी के बाद राष्ट्रीय तफ़तीशी एजेंसी (एनआईए) ने आरएसएस-बीजेपी के खेल हिंदू-मुसलमान के बीच खाई को और बढ़ाने का काम ईमानदारी से किया है। जिस आतंकी संगठन आईएस का भारत से लेना-देना नहीं है, अचानक उसके तार यहां के मुसलमानों से जोड़ दिये गये हैं और जगह-जगह से मुस्लिम युवकों की पकड़-धकड़ जारी है। मेवात भी इससे क्यों अछूता रहता, यहां से भी कई मुस्लिम युवकों को उठा लिया गया। मुस्लिम बहुल मेवात पर संघियों की नजरें पहले से रही हैं और वे लोग मेवात में दंगे की कोशिश करते रहते हैं। दिल्ली पुलिस में तो संघियों के इशारे पर एक नया गैंग खड़ा किया गया जिसे दिल्ली पुलिस मेवाती गैंग बताती है और उसी गैंग के नाम की खबरें तथाकथित मेनस्ट्रीम मीडिया में छपवाती है। पूंजीपतियों के अखबारों को पढ़ने वालों को यही पता चलता है कि मेवात में सिर्फ और सिर्फ गाय काटने का धंधा होता है और वहां का हर मुसलमान बीफ खाता है। यह तो सिर्फ मेवात की बात है। हालांकि अदालत में अभी तक एक भी केस साबित नहीं हो सका है कि मेवात के मुसलमान आईएस या आईएसआई से मिले हुए हैं और हर मुसलमान गाय काटता है।

खट्टर के आका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपनी विदेश यात्रा के कारण चर्चा में रहते हैं वो बेचारे भी विदेशियों भारत लाने के लिए अक्सर भटकते रहते हैं। उन्होंने मेक इन इंडिया का नारा दिया। उसका विज्ञापन पढ़ेंगे तो आपको भी लगेगा कि भारत से बेरोजगारी बस खत्म होने ही वाली है। मौजूदा केंद्र सरकार को दो साल होने जा रहे हैं लेकिन अभी तक एक भी बड़ी विदेशी कंपनी ने किसी भी तरह का विदेशी पूंजी निवेश भारत में नहीं किया है। औद्योगिक उत्पादन (आईआईपी) के सरकारी आंकड़े एक दिन पहले आये हैं, जिसमें बताया गया है कि भारत में औद्योगिक उत्पादन लगातार गिर रहा है यानी कारखानों में मैन्यूफैक्करिंग नहीं हो रही है। मतलब ये कि विदेशी पूंजी निवेश तो दूर अपने भी कल-कारखानों की हालत पतली है। इसका सीधा संबंध महंगाई से है। महंगाई होगी तो डिमांड घटेगी और उत्पादन प्रभावित होगा। बहरहाल, मोदी और खट्टर से विदेशी कंपनियों के वादे तो बहुत हैं लेकिन नजर कोई नहीं आ रहा। जिस विदेशी निवेश के आंकड़े सरकार आपको बताती है, वो है यहां की पहले से मौजूद कंपनियों में विदेशी कंपनियों का निवेश। इसका फायदा भी अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला को हो रहा है। अंबानी-अडानी अब हथियार की कंपनी खोलने जा रहे हैं तो विदेशी कंपनी ने इनसे गठजोड़ किया है यानी हथियार बनाने वाली इस्राइल और अमेरिका की कंपनियां अपना पूंजी निवेश अंबानी और अडानी की कंपनियों में ही करेंगी। अपनी कंपनी नहीं खोलेंगी। वापस बीफ पर लौटते हैं। दरअसल, बीफ का मामला अभी भी जानबूझकर उछाला जा रहा है। देश में बड़ी संख्या मांस न खाने वालों की है। लेकिन जो लोग मांस खाते हैं, उनकी संख्या मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं की है। यानी मांस का पूरा बिजनेस हिंदुओं के मांस खाने पर टिका है। बीफ उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा है लेकिन इस मुद्दे को धार्मिक रूप से जोड़ने और उठाने पर संघ और बीजेपी को फायदा मिलता है। हिंदू-मुसलमान के बीच दूरी और बढ़ जाती है। नफरत की आग और तेजी से सुलगती है। अखंड हिंदू राष्ट्र का सपना देखने वाले संघी इस स्थिति को अपने अनुकूल मानते हैं। इसकी वजह से भारत का सामाजिक भाईचारा भले ही बर्बाद हो जाए लेकिन राष्ट्र अखंड चाहिए। संघी भूल जाते हैं कि इस देश पर अंग्रेज दो सौ साल हुकूमत करके गये और उससे पहले मुगलों ने कई सौ साल हुकूमत की, क्या कभी उन लोगों ने भारत में जबरन खान-पान पर प्रतिबंध लगाया? अगर ऐसा हुआ होता तो इतिहास में हमें जरूर प्रमाण मिलता। जो इतिहास हमें यह बता सकता है कि औरंगजेब ने इतने हजार ब्राह्मणों की हत्या कराई, मंदिर गिरवाये, वही इतिहास हमें यह नहीं बता पाया कि भारत पर कई सौ साल राज करने वाले मुसलमानों ने कभी अपना खान-पान या रीति-रिवाज यहां के बहुसंख्यक हिंदुओं पर लादा हो। अब आइये भारत की मौजूदा स्थिति पर। ताजा आंकड़े बता रहे हैं कि मोदी सरकार ने अपनी सरकार बनाने के बाद नये बूचड़खाने खोलने और आधुनिकीकरण के लिए 15 करोड़ की सब्सिडी दी है। उनकी सरकार आने के बाद देश का मांस निर्यात बढ़ा है यानी बीफ बाहर भेजने पर हमें विदेशी मुद्रा खूब मिली है। नीचे आंकड़े देखिये -

खट्टर के आका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपनी विदेश यात्रा के कारण चर्चा में रहते हैं वो बेचारे भी विदेशियों को भारत लाने के लिए अक्सर भटकते रहते हैं। उन्होंने मेक इन इंडिया का नारा दिया। उसका विज्ञापन पढ़ेंगे तो आपको भी लगेगा कि भारत से बेरोजगारी बस खत्म होने ही वाली है। मौजूदा केंद्र सरकार को दो साल होने जा रहे हैं लेकिन अभी तक एक भी बड़ी विदेशी कंपनी ने किसी भी तरह का विदेशी पूंजी निवेश भारत में नहीं किया है। औद्योगिक उत्पादन (आईआईपी) के सरकारी आंकड़े एक दिन पहले आये हैं, जिसमें बताया गया है कि भारत में औद्योगिक उत्पादन लगातार गिर रहा है यानी कारखानों में मैन्यूफैक्करिंग नहीं हो रही है। मतलब ये कि विदेशी पूंजी निवेश तो दूर अपने भी कल-कारखानों की हालत पतली है। इसका सीधा संबंध महंगाई से है। महंगाई होगी तो डिमांड घटेगी और उत्पादन प्रभावित होगा।

4.8 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा पिछले साल सरकार को बीफ निर्यात से मिली

24 लाख टन का मीट निर्यात 2014-15 में भारत ने किया

58.7 फीसदी मांस निर्यात सिर्फ भारत से पूरी दुनिया को हुआ

65 देशों को भारत ने मीट का निर्यात किया, इनमें सबसे ज्यादा एशियाई व अफ्रीकी देश हैं।

45 फीसदी मांस वियतनाम भारत से मंगाता है यानी 100 फीसदी में से 45 फीसदी यहां से जाता है।

4 बड़े मांस निर्यातक हिंदू हैं। ये हैं अल-कबीर, जिसके मालिक सतीश और अतुल सभरवाल हैं। मुस्लिम नाम इसलिए रखा अपनी कंपनी का, जिससे एक्सपोर्ट में आसानी हो। दूसरी कंपनी है अरेबियन एक्सपोर्ट, जिसके मालिक सुनील करन हैं। ऐसा नाम जानबूझकर रखा गया है ताकि अरब देश भारत के हिंदू कंपनी का मांस खरीद सकें। तीसरी कंपनी है एमकेआर फ्रोजन फूड्स इसके मालिक मदन एबट हैं। चौथी कंपनी है पीएमएल इंडस्ट्रीज, जिसके मालिक ए.एस. बिंद्रा हैं। आरएसएस की जिस प्रयोगशाला गुजरात में मोदी का निर्माण हुआ, उस राज्य का मांस निर्यात बिजनेस लगातार बढ़ रहा है। अगर उसके आंकड़े भी हम यहां देंगे तो यह लेख लंबा हो जाएगा।

8 राज्य अभी भी ऐसे हैं, जहां गाय काटने की अनुमति है। ये राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। मोदी सरकार में हिम्मत हो तो यहां गोवध रोक कर दिखायें। असम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में गोवध अनुमति लेकर किया जा सकता है। अब देश की जनता फैसला करे कि बीफ-बीफ चिल्लाने वालों की राजनीति इन तथ्यों की रोशनी में कितनी सही है। हिंदू-मुसलमान को बांटने की यह साजिश बहुत गहरी है। संघ और बीजेपी इसे धार्मिक आधार पर ही बांट सकते हैं, वैसे इनके पास कोई हथियार नहीं है। सत्ता में बैठे लोगों को फायदा तभी होता है, जब लोग आपस में बंटे हुए हों, एक दूसरे के खिलाफ नफरत का माहौल हो।...जागो भारत जागो...सोने का वक्त नहीं है...

गतांक की चीर-फ़ाड़

मज़दूर मोर्चा का 1-15 फ़रवरी 2016 का अंक मिला जिसमें राष्ट्रीय, क्षेत्रीय व स्थानीय मुद्दों पर अनेक महत्वपूर्ण लेख पढने को मिले।

परमाणु बम व मिसाइलों के परीक्षण, कशमीर समस्या व भारत-पाक की आतंकवाद सम्बन्धी नीति के सन्दर्भ में लेख 'आतंकी मसूद अजहर का मंत्र बनाम फ़ुस्स मिसाइलों का गणतंत्र-71 में इंदिरा ने पाकिस्तान तोड़ा: 98 में अटल ने मूर्खता का पोखरण फ़ोड़ा' अति महत्वपूर्ण है। पोखरण- व बम परीक्षण से पहले भी भारत सैन्य शक्ति में श्रेष्ठ था जो 1971 के भारत-पाक युद्ध में सारी दुनिया के सामने स्पष्ट हो गया था। इस युद्ध में भारत ने पाक सेना का पूर्वी पाकिस्तान में आत्म समर्पण करने को मज़बूर करके पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए और एक अलग देश बांग्लादेश बना दिया था।

गौरतलब है कि अमरीका ने अपना सातवां जंगी जहाजी बेड़ा पाकिस्तान की सहायता के लिये बंगाल की खाड़ी में भेजा था परन्तु इन्दिरा गांधी व भारत सरकार पर अमरीकी जंगी जहाजी बेड़े का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और पाकिस्तान व अमरीका दोनों को मूंह की खानी पड़ी। भारत द्वारा 1974 में पोखरण- बम परीक्षण के बाद भारत पाकिस्तान से आगे निकल गया था। परन्तु 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी ने पोखरण - बम परीक्षण किया तो पाकिस्तान सरकार ने भी जवाब में परमाणु परीक्षण कर दिया। इसके बाद दोनों ही देशों में मिसाइलों का परीक्षण करने की होड़ लग गई और दोनों देश लगभग बराबरी के स्तर पर आ गए। आतंकी मसूद अजहर, हाफ़िज सईद जकीर रहमान लखवी आदि की भारत विरोधी आतंकी गतिविधियां ज़ारी है और भारत सीमा पार से आतंकी हमलों की जिम्मेदारी आतंकी संगठन बेखौफ़ अपने सिर पर लेते हैं।

प्रत्येक देश को अपनी रक्षा करने का हक है और रक्षा की तैयारी भी करनी चाहिए, परंतु इनको महिमंडित नहीं करना चाहिए। हथियारों का परीक्षण करके एक उन्माद खड़ा किया जाता है, जिसका विरोध करने वाले को राष्ट्रद्रोही कहा जाता है और मूल समस्याओं का नज़र अंदाज किया जाता है। भारत-पाक आतंकवाद समस्या की जड़ में असल में कशमीर समस्या है। साम्प्रदायिक उन्माद में न बहकर भौगोलिक स्थिति के मद्देनज़र राजनीतिक सूझबूझ से निर्णय लेने की आवश्यकता है और वह सर्वमान्य व्यवहारिक हल है कि कशमीर का जो हिस्सा भारत में है वह भारत में रहे और जो पाकिस्तान में हैं वह पाकिस्तान में रहे। इस निर्णय से दोनों देशों में शान्ति स्थापित होगी और दोनों की सैन्य शक्ति पर होने वाले खर्च में भी कमी आयेगी जिसमें दोनों देश अपनी-अपनी जनता की मूल समस्याओं जैसे गरीबी, शिक्षा, चिकित्सा, महंगाई आदि का निवारण कर सकेंगे।

हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में असहिष्णुता तथा सामंतवादी व्यवस्था व जातिवाद से पीड़ित और केन्द्रीय श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय, केन्द्रीय मानव संशाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी, एबीवीपी के नेताओं तथा नए वी सी प्रो. अप्पाराव के कुचक्रों से मजबूर रोहित बेगुला द्वारा आत्महत्या करने के लेख 'रोहित वेगुला कौन था?'रोहित वेगुला को किसने मारा?' में पूरा विवेचन किया गया है। गौरतलब है कि बगैर सबूत के पांच दलित छात्रों को एक सैमेस्टर के लिये निलंबित करने का विरोध करने पर पूर्व उप-कुलपति (वी सी) ने उन्हें बुलाकर सज़ा को नए सिरे से जांच होने तक के लिए वापिस ले लिया, परंतु नौ दिन बाद नए वी सी प्रो. अप्पा राव ने पांचों को होस्टल से निलंबित कर दिया तथा उनकी फ़ैलोशिप रोक दी। इस कार्यवाही से तंग आकर रोहित वेगुला द्वारा आत्महत्या करने का देश भर में कड़ा प्रतिरोध होने पर शेष चार छात्रों का निलम्बन वापिस ले लिया गया। स्पष्ट है कि यदि रोहित वेगुला जिन्दा होता तो उसका निलम्बन वापिस होता और उनका कोई दोष भी नहीं था। इन घटनाओं से प्रश्न उठते हैं कि रोहित की आत्महत्या के लिये कौन जिम्मेदार है, क्या उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही होगी तथा क्या वैचारिक खुलापन और लोकतांत्रिकता भारत की यूनिवर्सिटियों की पहचान बनी रह सकेगी?

गुजरात में नरेन्द्र मोदी व अमित शाह की साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण की नीति की सफलता व केन्द्र में सत्ता प्राप्ति के बाद दिल्ली व बिहार विधान सभा चुनावों तथा कई राज्यों के स्थानीय चुनावों में भाजपा की पराजय के बावजूद आरएसएस ने पुन: अमित शाह को राष्ट्रीय बनाया जिससे कि आगामी चुनावों में साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण की रणनीति द्वारा विजय प्राप्त की जा सके का लेख 'पिटे मोहरे को फ़िर भाजपा की कमान-साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण की रणनीति' में पूरा खुलासा किया गया है। मोदी व शाह ने जिस तरह गुजरात पर अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया था तथा संघ परिवार को खुली छूट नहीं दी थी, उस प्रयोग को राष्ट्रीय स्तर पर दोहराना उनके लिए कठिन होगा। यदि शाह को आगामी चनावों में कामयाबी नहीं मिली तो मोदी व शाह की जोड़ी को संघ के साथ अन्तरर्विरोध का भी सामना करना पड़ेगा।

मीडिया का प्रमुख कर्त्तव्य होता है जनता को सूचनाएं देना जागरूक करना व उनकी समस्याओं व मांगों को उठाना। परंतु मीडिया पर कॉरपोरेट जगत व पूंजीपतियों का नियंत्रण है, जिसका लेख 'आज़ाद देश में मीडिया के दलाल-कॉरपोरेट मीडिया और आवारा पूंजीवाद इस देश को गर्त में धकेल रहे हैं, जनता चुपचाप तमाशा देख रही है' में तर्क संगत वर्णन किया गया है। लोक सभा चुनाव में नरेन्द्र मोदी की छवि बनाने में कॉरपोरेट मीडिया ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अब मोदी उस कॉरपोरेट मीडिया व उन पूंजीपतियों की सहायता कर रहे हैं।

शनि शिग्नापुर शनि मन्दिर व सबरीमाला मन्दिर में औरतों के प्रवेश पर प्रतिबंध के विरुद्ध महिलाओं द्वारा आवाज़ उठाने के बावजूद रूढिवादी लोग इस परम्परा को छोड़ने को तैयार नहीं है। शनिमन्दिर में औरतों के वर्जित प्रवेश के सन्दर्भ में स्तम्भ 'खबरदार-शनि से काल्पनिक साक्षात्कार' के ज़रिए उचित कटाक्ष किया गया है।

मौजूदा पुलिस व्यवस्था व उसमें सुधार की आवश्यकता का लेख 'पुलिस का (अ) सामाजिक उत्पाद' में सटीक विश्लेषण किया गया है। पुलिस के व्यवहार में अब भी औपनिवेशिक कालीन क्रूरता दिखाई देती है। झंडेवालान स्थित आरएसएस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ पुलिस ने जो दमनकारी व क्रूर व्यवहार किया, उसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि यह जनतांत्रिक देश की पुलिस है। अन्य प्रकाशित लेख भी उच्च स्तरीय व प्रशंसनीय है।

-प्रो.जुगल किशोर गुप्ता